Chapter-4

बंजर भूमि और इराक के टैंकरों ने सोना उगला?

बीकानेर वर्ष में औसत 354 दिनों सूरज की किरणों से रोशन रहता है परन्तु फिर भी वहां के किसान हमेशा अँधेरे में डूबे रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्कॉटिश माँ के पुत्र और इटली ओरिंजिन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाडरा के राजस्थान में कदम रखते ही राजस्थान की कांग्रेस की गहतोल सरकार और केंद्र में उस समय स्थापित सोनिया जी की ऊँगलियों पर नाचने वाली मनमोहन सरकार की मदद से, अपनी किस्मत कैसे चमका सके किसानों को भूहीन करके, इस रहष्य को इस अध्याय में उजागर किया गया है। रॉबर्ट वाडरा ने राजस्थान की बंजर भूमि से अपने स्वयं के लिए सोना उगलवाने की जादुई कला अपनी सास सोनिया गांधी से सीखी है। क्या सोनिया गांधी के लिए सद्दाम हुसैन के समय इराकी पेट्रोल के टैकों ने सोना नहीं उगला था? क्या यह सबकुछ उस समय यू एन में कार्यरत शशि थरूर, भारत के उस समय विदेश मंत्री नटवर सिंह, ओत्तावियों क्वात्रोच्चि आदि की मदद से संभव नहीं हुआ था? इसका उत्तर इसी अध्याय के अंत में दिया जाने का प्रयास हुआ है।

गंजे को कंघी बेचना बनाम बंजर भूमि पर पैसे उगाना

गंजे सिर में बाल उगाना मुश्किल है उसी प्रकार बंजर भूमि मे फसल उगाना मुश्किल है परन्तु जादूगर राबर्ड वाड्रा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।

वे बंजर भूमि मे पैसा उगा चुके हैं। ए.आई.सी.सी. की बैठक मे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने कहा ' विरोधी पार्टियां कुछ भी कह सकती हैं। उनकी मार्केटिंग कला बहुत अच्छी है। वे मार्केटिंग के लिए हर प्रकार के नाम, साईन और गाने का प्रयोग कर सकते हैं। वे गंजों को कंघी भी बेच सकते हैं। अब कुछ नये लोगों का आगमन हुआ है जो गंजों को कंघी बेचते थे अब उन्हे हेयरकट की कला सिखा रहे हैं। उनके झांसों में मत आइये।''

राहुल गाँधी की उक्त टिप्पणी भाजपा पर की गई थी। इस टिप्पणी ने गंजे व्यक्तियों की भावनाओं को आहत किया है। बालों का झड़ना न झड़ना एक स्वाभाविक प्रकिया है। उत्तर महाराष्ट्र में जलगाँव जिले के अमालनेर कस्बे के गंजे लोग राहुल गाँधी के खिलाफ मोर्चा निकाल कर अपने विरोध का इजहार कर चुके हैं।

वाड्रा ने 10,000 एकड़ से भी अधिक बंजर भूमि सस्ते में खरीद कर कई गुना ज्यादा में बेचकर सिर्फ दो वर्षो में अप्रत्याशित अधिकाधिक लाभ अर्जित किया है।

राजस्थान प्रदेश का 60 प्रतिशत (208,110 स्क्वे. किमी.) भूभाग निम्न स्तर की बंजर भूमि है। यह मृत प्राय भूमि बिना पानी और मनुष्य के निवास रहित है। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर इस बंजर भूमि की कीमत 20.000 रू. से भी कम है।

क्या वोट बैंक गंजे सिर में उगते हैं

मुगले आजम खाँन ने लोक सभा चुनाव के समय अपने भाषण में कहा था कि भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह अपने सिर के बाल ही नहीं बचा सके तो भाजपा को क्या जीता पायेंगे या क्या हमारा प्रतिशोध ले पायेंगे।

2014 का पिछला लोक सभा चुनाव लोगों को सम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजित कर भाजपा विरोधी पार्टियां लड़ रही थी।

मुगले आजम खाँन की अमित शाह के ऊपर की गई उक्त टिप्पणी अमित शाह के उस कथन पर थी जिसमें खाँन के अनुसार मुजफ्फरनगर की सभा में ' प्रतिशोध मे वोटिंग ' करने का आह्वान अमित शाह ने किया था।

डीएलएफ के चेयरमैंन कुशल पाल सिंह के अनुसार उसने राजीव गांधी का नमक खाया है। इसलिए उसी एहसान का बदला उन्होंने लाख से 300 करोड़ रूपये तीन वर्षो में इकट्ठा करने में कानून की ऑखों में धूल झोंक कर मदद की। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ में नहीं उगते। इसका मतलब क्या यह है की पैसे बालों में उगते हैं? क्या इसका मतलब है कि पैसे मुगले आज़म खान, सोनिया गांधी आदि राजनीनिज्ञों के हेयर में उगते हैं?

पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने 17 अगस्त 2013 को कहा कि रॉबर्ट वाडरा जमीन सौदे की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री हुड्डा के शासनकाल में 70 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। रॉबर्ट वाडरा जमीन सौदे में आईएएस अशोक खेमका का निर्णय सही हैं। मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वाडरा की कंपनी ने फरवरी 2008 में 7 करोड़ में जमीन का सौदा किया। मार्च में इसे 57 करोड़ रूपये में बेंच दिया। सात करोड़ का चैक भी बांउस हो गया।

हरियाणा के बाद अब राजस्थान में रॉबर्ट वाडरा का भूमि हड़प अभियान (जमीन का घोटाला) सामने आया है, रॉबर्ट वाडरा पर आरोप है कि राजस्थान के बीकानेर जिलें मे जमीन खरीदने के लिए उन्होंने कानून तोड़ा। रॉबर्ट वाडरा की जमीन खरीदी का मसला इसलिए गंभीर सवाल उठाता है कि राजस्थान सरकार ने भूमि कानून तक बदल दिया। क्या औंने–पौंने दाम पर खरीदी जमीन से मोटा मुनाफा कमा लेना वाडरा की अच्छी किस्मत है या फिर सरकार से मिली जानकारी ने उनकी किस्मत चमका दी।

राजस्थान के बीकानेर जिले में बंजर जमीन से रॉबर्ट वाडरा को फायदा पहुंचा, भले ही रॉबर्ट वाडरा ने लैंड़ सीलिंग एक्टर में संशोधन से ठीक पहले सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी हो, लेकिन आज तक ने उन चार लेन–देन के मामले को उजागर किया है, जिसमें 321.8 एकड़ जमीन ली गयी, जबकि इजाजत तो सिर्फ 175 एकड़ जमीन रखनें की है।

राजस्थान के बीकानेर जिले में बंजर जमीन से रॉबर्ट वाडरा को फायदा पहुंचा, भले ही रॉबर्ट वाडरा ने लैंड़ सीलिंग एक्टर में संशोधन से ठीक पहले सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी हो, लेकिन आज तक ने उन चार लेन–देन के मामले को उजागर किया है, जिसमें 321.8 एकड़ जमीन ली गयी, जबकि इजाजत तो सिर्फ 175 एकड़ जमीन रखनें की है।

सितंबर 2010 से पहले 321.8 एकड़ जमीन खरीदी गयी, राजस्थान लैंड़ सीलिंग एक्ट के तहत सितंबर 2010 से पहले 175 एकड़ अधिकतम जमीन रखने की इजाजत थी।

बीकानेर जिले के कोयालत इलाके के बस्ती चौनन गांव में वाडरा के फंटमैन महेश नागर ने 2009 में 218 एकड़ जमीन खरीदी। नागर ने ही बीकानेर के कोलायत इलाके में रॉबर्ट वाडरा के लिए सारे डील किये। 9 अप्रैल, 2009 को रीयल अर्थ इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से महेश नागर ने 218 एकड़ जमीन खरीदी। नागर का वाडरा का रिश्ता यह था कि वह रीयल अर्थ प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर था, विकेता अविजीत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के विनीत असोपा थे, जमीन का खसरा नंबर 58,63।

जून 2009 में ही वाडरा ने गजनेर गांव में 36 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी, लैंड डील दस्तावेजों से यह पता चलता है कि महेश नागर ने ब्लू ब्रीज़ प्राइवेट ट्रेड़िंग लिमिटेड की तरफ से ये जमीन खरीदी थी। इस कंपनी में वाडरा का नाम बतौर डायरेक्टर है। इसमें ब्लू ब्रीज़ प्राइवेट ट्रेड़िंग लिमिटेड की तरफ से महेश नागर ने 36.87 एकड़ जमीन खरीदी। यहां वाडरा से नागर का रिश्ता था कि वह ब्लू ब्रीज़ प्राइवेट ट्रेड़िंग लिमिटेड का डायरेक्टर था। जमीन का खसरा नंबर 657/445 था।

रीयल अर्थ में वाडरा के पास 99 फीसदी इक्विटी है, जबकि बांकी एक फीसदी इक्विटी उनकी मां मौरीन के पास है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक,ब्लू ब्रीज़ प्राइवेट ट्रेड़िंग लिमिटेड में सिर्फ दो शेयरहोल्डर्स हैं–राबर्ट वाडरा और उनकी मां मौरीन।

कंपनी के असली मालिक वाडरा हैं। रीयल अर्थ में बड़ा हिस्सा राबर्ट वाडरा (99%) के नाम है। उनकी मां मौरीन वाडरा के पास 1% है।

आजतक के पास एमएस रीयल अर्थ इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी चेक की कापी है, जिस पर रॉबर्ट वाडरा के दस्तखत हैं। जमीन खरीदने के लिए दिए गये ये चेक साबित करते हैं कि अपने फंटमैन महेश नागर के जरिए सारा काम वाडरा करा रहे थे।

9 अप्रैल 2009 को अविजीत एग्रों (मालिक विनीत असोपा) को 91.50.000 रूपये की रकम चुकायी गयी। चंक नंबर था 759382 और इस पर रॉबर्ट वाडरा के साइन थे। 9 अप्रैल को ही सरिता बोथरा (विनीत असोपा के पास वाले प्लॉट की मालकिन) को चैक नंबर 759384 के जरिए 8.50.000 रकम दी गई, इस पर भी वाडरा के ही साइन थे।

ये लेनदेन राजस्थान इंपोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रिकल्चर होल्ड्रिंग्स एक्ट, 1973 का साफ साफ उल्लंघन है, क्योंकि वाडरा ने अप्रैल 2009 में 175 एकड़ जमीन रखने की अधिकतम सीमा को पार किया।

वाडरा ने अप्रैल 2009 और अगस्त 2010 के बीच 321 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी, ये राजस्थान इंपोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रिकल्चर होल्ड्रिंग्स एक्ट, 1973 का उल्लंघन था, रेगिस्तानी इलाकों में वाडरा के लिए लैंड सीलिंग को अधिकतम सीमा तक खींचा गया, कानून के मुताबिक रेगिस्तानी और अर्थ रेगिस्तानी इलाकों में 125 से 175 एकड़ जमीन रखने की इजाजत है।

अशोक गहलोत के मुख्य मंत्रीत्व वाली कांग्रेस सरकार दो मायने में अभियुक्त नजर आती है, पहले जब 2009 में वाडरा राजस्थान में जमीन खरीद रहे थे, तब उसे नजरअंदाज कर दिया, और अब जमीन खरीद ली, तब जमीन एक्ट में संशोधन करके उसे कानूनी तौर पर वैधता दे दी।

वाड्रा के लिए बदला कानून?

सितंबर 2010 में अशोक गहलोत की राज्य सरकार ने तीन दशक से भी ज्यादा पुराने कानून में संशोधन किया, साथ ही जमीन पर सीलिंग भी खत्म कर दी। संशोधन में सभी पुराने अधिग्रहण को सही ठहराने के लिए जरूरी नियम जोड़ दिये गये, ताकि उस इलाके में वाडरा ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकें।

"2009 में वाडरा राजस्थान में जमीन खरीद रहे थे, तब अशोक गेहलोत की कांग्रेस सरकार ने अपनी आंखे बंद रखी और जब वाडरा ने जमीन खरीदी तो जमीन एक्ट में संशोधन करके उसे मंजूरी भी दे दी..... ये बात दर्शाती है की अशोक गेहलोत सरकार भी वाडरा को मदद कर रही थी।" सितंबर 2010 में राज्य सरकार ने तीन दशक से भी ज्यादा पुराने कानून में संशोधन किया साथ ही जमीन पर सीलिंग भी खत्म कर दी, संशोधन में सभी पुराने अधिग्रहण को सही ठहराने के लिए जरूरी नियम जोड़ दिये गये, ताकि उस इलाके में वाडरा ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकें।'

जहां वाडरा के उल्लंघन को कानूनी जामा पहनाने के लिए कांग्रेस शासित राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव कर दिया, वही करीब तीन साल तक वो सोलर पॉलिसी पर भी बैठी रही, ये वो दौर था, जब वाडरा ने इस इलाके में बड़ा लैंड बैंक तैयार कर लिया था।"

* अप्रैल 2009 वाडरा ने कोलायत इलाके में जमीन खरीदी शुरू की।
* नवंबर 2009 केंद्र का जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू।
* 2009 सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र का राज्यों को लैंड बैंक बनाने का निर्देश।
* 2009 से 2011 के बीच वाडरा ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली।
* अप्रैल 2011—राजस्थान सरकार की सोलर पॉलिसी शुरू।
* जहां सोलर प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव आया, वहां की बंजर जमीन भी महंगी हो गयी।

* सूरज की किरणों में वाड्रा भूमि घोटाले के काले धन्धे स्पष्ट दिखे।

''यहीं से वो कहानी शुरू होती है कि केसे बीकानेर में वाडरा ने मोटा मुनाफा कमाया, उन्होंने बीकानेर के कोलायत इलाके में 81.35 एकड़ जमीन खरीदकर बाद में छह गुने दाम पर सोलर पॉवर प्रोजेक्ट शुरू करने की।

इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं–
–क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में जमीन खरीदने के लिए वाडरा से साठ–गांठ की।
–क्या राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव इसलिए किया ताकि तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदने वाले वाडरा का सौदा कानून जायज हो सके।
–क्या जमीन खरीदने से पहले ही वाडरा को उस इलाके में सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स आने की जानकारी मिल गयी थी।
–तीन साल में सरकार लैंड बैंक बनाने में क्यों नाकाम रही।
–वाडरा के मुद्दे पर बीजेपी ने संसद में हंगामा किया, आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने जानबूझकर गड़बड़ी की। वहीं कांग्रेस किसी भी अनियमितता से इनकार कर रही है।

9 अप्रैल 2009 को अविजीत एग्रों (मालिक विनीत असोपा) को 91.50.000 रूपये की रकम चुकायी गयी। चेक नंबर था 759382 और इस पर रॉबर्ट वाडरा के साइन थे। 9 अप्रैल को ही सरिता बोथरा (विनीत असोपा के पास वाले प्लॉट की मालकिन) को चैक नंबर 759384 के जरिए 8.50.000 रकम दी गई, इस पर भी वाडरा के ही साइन थे।

वाली इंडो–फ्रेंच कंपनी फोनरॉक सारस (Fonroche Saaras) को बेच दी, सिर्फ इसी एक ट्रांजेक्शन से वाडरा ने 612 फीसदी लाभ कमाया, दो साल के भीतर जमीन की कीमत छः गुना बढ़ गयी।''

विवरण :
जून 2009
तारीख– 4 जून,2009
खसरा नंबर – 657/445
गांव 7 गजनेर
क्षेत्र – 37.3 एकड़
कीमत – 8.7 लाख रूपये

खरीदार – महेश नागर
कंपनी – ब्लू ब्रीज़ ट्रेड़िंग प्राइवेट लिमिटेड
बेचा गया – फोनरॉक सारस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
तारीख – 23 मई,2012
बेचने की कीमत – 1.01.62.599 रूपये
लाभ – 92.9 लाख रूपये (खरीद दाम से 11 गुना ज्यादा)

'' 4 जून 2009 को वाडरा के फंटमैन ने एक बार फिर गजनेर गांव में ही 27.5 एकड़ जमीन खरीदी और उसे छह गुने दाम पर बेच दिया, उन्होंने 13 लाख से कुछ ज्यादा दाम पर जमीन खरीदकर 75 लाख से ज्यादा कीमत पर फोनरॉक राजहंस को बेच दिया।''

खसरा नंबर– 658/445 गांव– गजनेर
क्षेत्र – 27.5 एकड़
कीमत – 13.2 लाख रूपये
खरीदार – महेश नागर
कंपली – ब्लू ब्रीज़ ट्रेड़िंग प्राइवेट लिमिटेड
बेचा गया – फोनरॉक राजहंस प्राइवेट लिमिटेड
तारीख 7 23 मई, 2012
बेचने की कीमत – 75 लाख रूपये
लाभ – 62 लाख रूपये (खरीद दाम से 6 गुना ल्यादा)

मार्च 2010
गांव – गजनेर
क्षेत्र – 81.3 एकड़
कीमत 28 लाख रूपये
खरीदार – प्रफुल्ल दाहिया की तरफ से महेश नागर
कंपनी – स्काइलाइट रियल्टी
बेचा गया – फोनरॉक सारस के प्रमोद राजू
तारीख –23.05.2012
जमीन की कीमत – 1.99 करोड़

'' 4 जून 2009 को गजनेर में वाडरा के फंटमैन महेश नागर ने 37.29 एकड़ जमीन खरीदी, फिर उसे तीन साल में ही ग्यारह गुना से भी ज्यादा दाम पर इंड़ो–फ्रेंच कंपनी फोनरॉक सारस एनर्जी प्रावेट लिमिटेड को बेच दिया।''

राजस्थान में 60% मृत प्राय बंजर भूमि है। बीकानेर व अन्य जगहों के सोलर पावर केंद्र के नजदीक की भूमि को गहलोत सरकार की साइ–गांठ से एक षड़यंत्र के तहत वाडरा ने सस्ते रेट में खरीदना प्रारम्भ कर दिया। उन स्थानों पर कई भूमि तो 20.000 रूपये से भी कम रेट में वाडरा द्वारा खरीदी गई। नमूनू के तौर पर हम एक उदाहरण यह ले सकते है कि 30 हेक्टर भूमि जो 4.45 लाख में खरीदी गई उसकी कीमत सिर्फ 2 वर्षो में ही 2 करोंड़ के लगभग हो गई।
बंजर भूमि की कीमत में यह वृद्धि सोनिया गांधी के दामादश्री वाडरा की गहलोत सरकार से साठ–गांठ का ही परिणाम है। वाडरा को यह चाल बाजी करने की सुविधा गहलोत सरकार ने ही दी कि वाड्रा धार के रेगिस्तान की बंजर भूमि को खरीदता जाये जिसे उसके तुरन्त बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार सोलार केंद्र के रूप में परिवर्तित करने वाली है।

सोनिया गांधी के दामाद को भ्रष्ट धन उगाने की कारस्तानी करने में मदद गहलोत सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की उस समय की मनमोहन सरकार ने भी सोनिया गांधी के इशारे पर प्रदान की। सोनिया गांधी के इशारे पर उस समय चल रही केंद्र सरकार उस समय तक अपनी नई सौर नीति की घोषणा नहीं की थी। जब वाडरा, 2009 में राजस्थान में अपने रियल एस्टेट निवेश शुरू किया, उस समय में इसके बारे में केवल एक संकेत था कि प्रधानमंत्री सिंह के बयान के जरिये (30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना की शुरूआत करते हुए) कि नई ऊर्जा नीति में, ''सूरज मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा, सूरज सभी ऊर्जा का मूल स्रोत है।''

वाडरा की चालबाजी बीकानेर की कोलायत तहसील के गजनेर में रॉबर्ट वाडरा की कंपनियों ने भारी मात्रा में जमीनें कौड़ियों के दाम खरीदी। कुछ सौदों में तो रॉबर्ट वाडरा ने खुद के हस्ताक्षरों से स्टेंडर्ड चार्टड बैंक के चेक जमीन मालिकों को दिए हैं। उदाहरणार्थ सरिता बोथरा को 8.5 लाख का चैक 2.5 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिए दिया। रॉबर्ट वाडरा सालों तक बजर जमीन की कौड़ियों के दामों में खरीद करते रहे, क्योंकि उन्हें पूर्व सूचना मिल गई थी कि यहां सौर ऊर्जा हब तैयार करने की परियोजना की घोषणा होने वाली है। लेकिन किसानों को आभास नहीं था कि उनकी बंजर जमीन उनके दिन फिरा सकती है।
राज्य सरकार की और केंद्र की कांग्रेस सरकारों द्वारा वाडरा को अपार लाभ अर्जित करने के लिए कानून बनाने या कानून में परिवर्तन करने के संकेत

पहले से ही दे दिया जाता था आक्सर संकेत पाते ही वाडरा अपने दलालों विशेषकर नागर बंधुओं द्वारा भूमि कम दरों में खरीदकर कई गुना कीमत में बेचना प्रारम्भ कर देते थे। कुछ स्थानों पर वह व्यावहारिक रूप से भूमि का एकाधिकार केता और विकेता रहा है, उसने एजेंटों और कंपनियों के माध्यम से, वह सीधे सौर ऊर्जा क्षमता के साथ क्षेत्रों में छोटे और बड़े किसानों से भूमि को कम कीमत में खरीदा और कई गुना कीमत में बेंचा। उदाहरण के लिए कोलायत में यह जादुई खेल कांग्रेस सरकारों की जादुई छड़ी से बखूबी हुआ। वहां की 90% बंजर भूमि नाम मात्र कीमत देकर किसानों से हड़प ली और उस भूमि का वह एकाधिकार विकेता रहा।

केवल राज्य सरकार – और केंद्र सरकार तथा वाडरा ही को जानकरी थी कि निकट भविष्य में विद्युत उत्पादन केंद्रों के स्थापित होने के तुरंत बाद उनके आसपास की भूमि की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी।

राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में भूमि बैंक स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। परन्तु विद्युत उत्पादन क्षेत्रों और भूमि बैंकों के आसपास की भूमि का अधिग्रहण एक सोंची समझी चालबाजी के तहत नही किया गया ताकि यहां की भूमि को वाडरा औने पौने दाम पर खरीद सके जो कि बाद में वह जमीन वाडरा के लिए सोना उगलने लगेगी। इस विषय पर विस्तार से तथ्यों के साथ हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं।

अब हम चर्चा करेंगे सद्दाम हुसैन के समय इराकी पेट्रोल के टैंकों ने सोना कैसे उगला था। क्या यह सबकुछ उस समय यू एन में कार्यरत शशि थरूर, भारत के उस समय के विदेश मंत्री नटवर सिंह, ओत्तावियो क्वात्रोच्यि आदि की मदद से संभव नहीं हुआ था?

वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के उपरांत कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार का आगमन सोनिया गांधी के नाम के अनुरूप गांधी वाडरा परिवार के लिए सोना उगलवाने के लिए विशेषकर हुआ था। आयल फॉर फूड कांड की जाँच कर रहे वोल्कर ने इा कांड में AWB लिमिटेड और भारत की कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों लिया था? यह कंपनी इराक को मानवीय गुड्स की सबसे बड़ी निर्यातक थी। इसी के माध्यम से यू.पी.ए सरकार ने भी इराक सरकार से संपर्क साधा।